2 SEP 2019

GENERAL STUDIES (Module – 8)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/19 (N-M)–M–GS18

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Sunil Kumar Dhanwarta **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** +7059

Center & Date: DELHI & 02/09/2019 **UPSC Roll No.** *(If allotted)*: 0815872

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
*इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा **हिन्दी** और **अंग्रेज़ी** दोनों में छपे हैं।*
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

खंड - क/ SECTION - A

1. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएँ कौन-सी हैं? यह विधेयक देश की पारदर्शी शासन व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? (150 शब्द) 10

What are the key features of the Right to Information (Amendment) Bill 2019? How does the Bill affect the transparency regime in the country? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था जो सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

2019 के संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ :-

(i) ~~प्रमुख~~ मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति शर्तें, कार्यकाल व सेवा शर्तें का निर्धारण अब केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ii) अब सूचना आयुक्तों को निर्वाचन आयुक्तों के समान दर्जा प्राप्त नहीं होगा।

(iii) इनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रभाव :-

(i) सूचना आयुक्तों की नियुक्ति इत्यादि में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ने से उनकी स्वतंत्रता कम हो सकती है → सरकार के खिलाफ सूचनाओं को छुपाया जा सकता है।

(ii) कई 'NGOs' द्वारा इस संशोधन का विरोध किया जा रहा है। उनका मत है कि यह 'RTI' की मूल भावना को समाप्त कर देगा।

पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुशासन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं और स्वस्थ ~~लोकतंत्र~~ लोकतंत्र में इनका होना अत्यंत आवश्यक है अतः इस कदम पर गंभीर विचार- विमर्श की आवश्यकता है तथा इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये। सामान्यतः संशोधन प्रक्रिया की आलोचना क्यों की जाती है? (150 शब्द) 10

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why this amendment procedure has been often criticized? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

अनुच्छेद 368 के अंतर्गत तीन प्रकार की संशोधन प्रक्रियाओं का समावेशन किया गया है।

(i) सामान्य संशोधन प्रक्रिया

- साधारण बहुमत द्वारा पारित होना
- जैसे - नये राज्यों का निर्माण

(ii) विशेष संशोधन प्रक्रिया

- उपस्थित व मत देने वालों के 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल संख्या का बहुमत
- उदाहरण. मूल अधिकार में संशोधन

(iii) विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया

- विशेष संशोधन प्रक्रिया तथा आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन
- उदाहरण - राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया
  - 7वीं अनुसूची

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संशोधन प्रक्रिया की आलोचना के कारण

(i) ~~राज्य~~ नये राज्यों के निर्माण में राज्यों की ~~निर्णायक~~ कोई प्रभावी भूमिका नहीं

(ii) विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया → एक लंबी प्रक्रिया

(iii) जनता की राय का समावेशन नहीं

(iv) राज्यसभा का अनावश्यक गतिरोध

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3. 'जनहित का प्रत्येक विषय जनहित याचिका का विषय नहीं हो सकता है'। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

'Every matter of public interest cannot be a matter of public interest litigation'. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी. एन. भगवती द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह लोकहित के मुद्दों के समाधान का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

पक्ष में तर्क :-

(i) कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में सहायक
(जैसे – दिल्ली में CNG बस शुरू करने का निर्णय
→ BSVI लागू करने का निर्णय

(ii) स्वतः संज्ञान के माध्यम से अनेक मुद्दों का समाधान

(iii) सामान्यतः समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा में सहायक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जनहित याचिका के विपक्ष में तर्क

(i) इससे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होता है।
↳ कानून बनाने का अधिकार विधायिका को परंतु न्यायालय द्वारा कानून बनाना जैसे विशाखा दिशानिर्देश, तीन तलाक के मुद्दे पर दिशा-निर्देश।

(ii) इससे कार्यपालिका के ऊपर जनता का विश्वास कम होता है।
इसलिए न्यायालय को उन्हीं मुद्दों में जनहित याचिका स्वीकार करनी चाहिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो तथा कार्यपालिका लंबे समय से इस पर कोई कदम नहीं उठा रही हो।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

4. भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कई सीमाओं से ग्रस्त है। विवेचना कीजिये।
(150 शब्द) 10

Parliamentary control over executive in India is riddled with several limitations. Discuss.
(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कार्यपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उस पर संसदीय नियंत्रण का होना आवश्यक है।

प्रमुख अंग :-

(i) स्थगन प्रस्ताव
(ii) निंदा प्रस्ताव
(iii) विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव
(iv) अविश्वास प्रस्ताव
(v) कटौती प्रस्ताव

सकारात्मक पक्ष

(i) सरकार को जवाबदेह बनाता है।
(ii) कई बार सरकार को गंभीरता से मुद्दों पर विचार करने को बाध्य करता है।
(iii) कटौति प्रस्ताव के माध्यम से वित्तीय जवाबदेही

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

विपक्ष

(i) सरकार पर ज्यादा दबाव नहीं बना सकते

(ii) सरकार यदि बहुमत में है तो इनका सरकार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता

(iii) विपक्ष के कमजोर होने पर यह और कमजोर हो जाता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

5. राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच विभेदन कीजिये। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने हेतु दवाब समूहों द्वारा कौन-से प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं? (150 शब्द) 10

Distinguish between political parties and the pressure groups. What are some of the prominent ways in which pressure groups try to influence the policies of the government? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

दबाव समूह सरकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

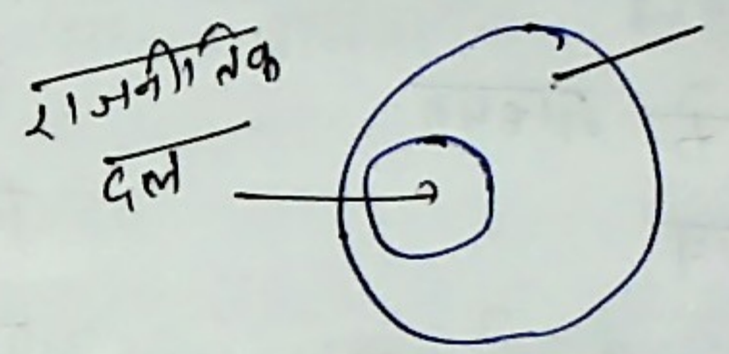

राजनीतिक दल	दबाव समूह
(i) राजनीति में भाग लेते हैं।	(i) सामान्यतः राजनीति के बाहर रहकर कार्य
(ii) सरकार में शामिल होते हैं	(ii) ~~सामान्य~~ ये सरकार में शामिल नहीं होते हैं।
(iii) ये दबाव समूहों का ही एक उपसमूह हैं।	(iii) इसमें NGOs, मीडिया, सिविल समाज, राजनैतिक दल सब शामिल

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

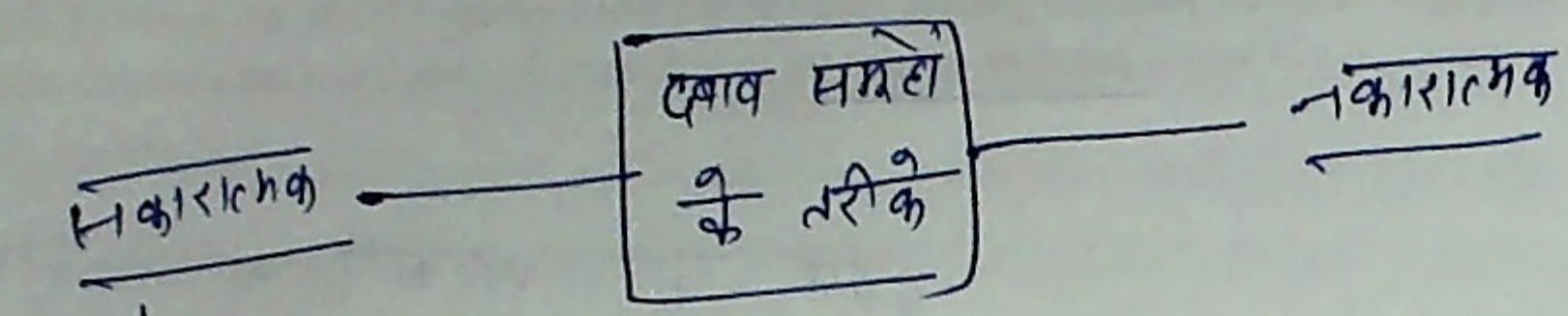

सकारात्मक

→ शांतिपूर्ण हड़ताल एवं प्रदर्शन

→ याचिका के माध्यम से दबाव

→ न्यायिक समीक्षा द्वारा दबाव

→ सोशल मीडिया पर समर्थन द्वारा दबाव

→ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया द्वारा दबाव

नकारात्मक

→ हिंसक गतिविधियों द्वारा दबाव (जैसे आतंकवादियों द्वारा विमान हाइजैक कर अपनी बात मनवाना)

→ गैर कानूनी तरीकों का प्रयोग करना जैसे नक्सलवादी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

6. जहाँ एक ओर सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 भारत में सरोगेसी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता है, वहीं दूसरी ओर इसकी कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

While the Surrogacy (Regulation) Bill 2019 does address various issues relating to surrogacy in India, its drawbacks can not be overlooked. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सरोगेसी बिल के प्रमुख प्रावधान-

(i) सरोगेटरी माँ पारिवारिक संबन्धों में होनी चाहिए

(ii) शादी-शुदा जोड़े को विवाह के 5 वर्ष के पश्चात ही इसकी अनुमति तथा बाकी विकल्पों की असफलता के बाद ही इसको अपनाना

(iii) वाणिज्यिक लेन-देन को अवैध एवं दण्डात्मक घोषित करना

(iv) सरोगेसी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना → निरीक्षण बनाना तथा उनको लागू करवाना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लाभ

→ निःसंतान दंपत्तियों को संतान सुख

→ सरोगेसी के वाणिज्यीकरण पर रोक

→ दबाव से सरोगेसी पर रोक

कमियाँ

→ सरोगेसी की प्रक्रिया अत्यंत जटिल हो गई है → सरोगेसी माँ का मिलना अत्यंत कठिन

→ समलैंगिकों को सरोगेसी की सेवाओं की अनुमति नहीं → इनके समानता के अधिकारों का उल्लंघन

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7. यद्यपि स्थानीय चुनाव लड़ने के लिये न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इस कदम के साथ मौजूदा चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द) 10

While mandating minimum education criteria for contesting local elections is a progressive move, the associated challenges with this move can not be ignored in the current scenario. Comment.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में राजस्थान में स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पक्ष में तर्क-

(i) शिक्षित राजनेता → सभी प्रशासनिक व कानूनी प्रक्रियाओं की बेहतर जानकारी
↓
बेहतर कार्य संचालन

(ii) लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करेगा।

(iii) डिजिटल संचार का युग - न्यूनतम योग्यता आवश्यक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

विपक्ष में तर्क

(i) जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा नेता ही एक अच्छा नेता हो

(ii) यदि स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद भी कोई आशिक्षित है तो वह राज्य की असफलता

(iii) वंचित वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन

↓

SC, ST, , महिलाओं की साक्षरता कम

↓

वे अयोग्य हो जाएंगे

(iv) इसमें शिक्षा व्यवस्था को पहले समावेशी व दुरुस्त बनाना आवश्यक।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

8. कठोर दंड देने के आडंबर में हमें पोक्सो (POCSO) अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं से ध्यान नहीं भटकाना चाहिये। POCSO (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये। (150 शब्द) 10

The rhetoric over severe punishments should not deflect our attention from the problems related to implementation of POCSO Act so far. Discuss in the context of POCSO (Amendment) Bill 2019. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

POSCO संशोधन के प्रावधान

- 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर मृत्युदंड की सजा
- 12-18 वर्ष की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान
- फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय
- बलात्कार की परिभाषाओं को पुनर्भाषित करना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कठोर दण्ड के पक्ष में तर्क

(i) निवारक की भूमिका

(ii) लोगों में कानून का भय

(iii) पीड़ित को समुचित न्याय

क्रियान्वयन संबन्धी समस्याएँ

(i) जाँच की गुणवत्ता निम्न

(ii) राजनीतिक हस्तक्षेप

(iii) धीमी न्यायिक प्रक्रिया

(iv) कठोर दण्ड से जरूरी नहीं कि अपराध कम हो (शोध से स्पष्ट)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

9. हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओ.आई.सी.) की बैठक में भारत की भागीदारी को 'ऐतिहासिक' क्यों कहा गया है? भारत के लिये इसका क्या भू-राजनीतिक महत्त्व है? (150 शब्द) 10

Why the recent participation of India in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting has been termed 'historic'? What is its geopolitical significance for India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

पहली बार OIC में भारत को

निमंत्रण

महत्व

- पाकिस्तान पर दबाव
- आतंकवाद के खिलाफ कदम
- इस्लामिक देशों का विश्वास जीतना
- ऊर्जा सुरक्षा. सतत् तेल व गैस आपूर्ति
- क्षेत्र में प्रवासियों के हितों की रक्षा
- मध्य-पूर्व के भू-राजनीतिक मुद्दों में भारत की भागीदारी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक समर्पित भारत-प्रशांत विभाग की स्थापना की है। इस संदर्भ में भारत के लिये भारत-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Recently the Ministry of External Affairs has setup a dedicated Indo-Pacific division. In this context examine the geo-political significance of the Indo-Pacific region for India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत: प्रशांत क्षेत्र का महत्व

- चीन का प्रभाव रोकना
- नेट सुरक्षा प्रदाता बनना
- व्यापारिक मार्ग
- प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता
  - जैविक
  - तेल
- आतंकवाद व पायरेसी सुरक्षा
- आपदा प्रबंधन
- ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा
- नौसैनिक शक्ति बढ़ाना

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. भारत में हाल ही में कौन-से चुनाव सुधार लागू किये गए हैं? आपके अनुसार चुनाव सुधार संबंधी किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना अभी शेष है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी संदर्भ में भारत में समय-समय पर अनेक सुधार लागू किए जाते रहे हैं।

हाल ही के प्रमुख सुधार :-

(i) चुनावी बॉंड
- राजनीतिक दलों को चंदा देने हेतु
- बैंक द्वारा बॉंड के माध्यम से
- काले धन की समस्या का समाधान

(ii) लोकसभा चुनावों में वीवीपैट (VVPAT) का प्रयोग
- किसी संदिग्धता की स्थिति में वोटों के सत्यापन हेतु
- जनता में 'EVM' मशीन के प्रति विश्वास जगाने हेतु

(iii) चुनाव प्रत्याशियों की धन संपत्ति का खुलासा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

(iv) सेवा वोटर्स के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक मत पत्र' का विकास

(v) EVM पर प्रत्याशी के चुनाव चिह्न के साथ-साथ उनकी फोटो लगाना

परंतु इनके अलावा भी अनेक क्षेत्र हैं जहाँ व्यापक चुनाव सुधार की अपेक्षा है। ये हैं-

(i) चुनावों में ~~बेहिसाब~~ बेतहासा खर्च पर रोक लगाना

(ii) मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और सोशल मीडिया

(iii) एक राष्ट्र, एक चुनाव का सिद्धांत

(iv) चुनावों में राज्य द्वारा वित्त पोषण

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(v) अपराधियों का चुनाव लड़ना अर्थात् राजनीति का अपराधीकरण

(vi) चुनाव आयोग को दण्डात्मक शक्तियाँ प्रदान करने के संदर्भ में

→ भ्रष्ट प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने के संदर्भ में

→ चुनाव आयोग की अवमानना के संदर्भ में

(vii) राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा

चुनाव सुधारों के लिए जनता एवं राजनेताओं के बीच एक विस्तृत विचार-विमर्श होना चाहिए तथा शीघ्र ही लंबित पड़े सुधारों को लागू किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव आयोजित किए जा सके।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. भारत में मानव अधिकार आयोगों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं पर चर्चा करते हुए इन संस्थानों को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 15

While discussing structural and practical limitations faced by Human Rights Commissions in India, suggest measures to strengthen these institutions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई थी जो भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों के संदर्भ में जाँच करता है तथा आवश्यक सलाह प्रदान करता है।

मानवाधिकार आयोग के समक्ष संरचनात्मक समस्याएँ

(i) मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर केवल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की ही नियुक्ति → परंतु अब संशोधन

(ii) इसके पास स्वयं के जाँच दल एवं मानव संसाधनों तथा समर्पित सचिवालय की कमी है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(iii) इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है → हस्तक्षेप की आशंका हो सकती है।

(iv) इसके सदस्यों में पर्याप्त मात्रा में न्यायिक सदस्यों की कमी

व्यवहारिक सीमाएँ

(i) आयोग के पास केवल सलाहकारी शक्तियां, दण्डात्मक शक्तियों का अभाव

(ii) भारत के विस्तृत भौगोलिक विस्तार को देखते हुए इनके पास पर्याप्त मात्रा में सदस्यों का अभाव

(iii) राज्यों के मानवाधिकार आयोगों के बीच तथा राज्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बीच पर्याप्त समन्वय का अभाव

(iv) इसके सुझावों पर संसद में चर्चा नहीं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

संस्थान की सुदृढ़ता के लिए उपाय

(i) मानवाधिकार आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019 का समुचित क्रियान्वयन (अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अलावा भी नियुक्ति संभव

(ii) आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन एवं जाँच दल हो

(iii) समन्वय होना चाहिए

(iv) आयोग को कुछ मात्रा में quasi-judicial शक्तियाँ भी दी जा सकती हैं।

इसके साथ ही आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इसे सरकार के हस्तक्षेपों से मुक्त करना चाहिए ताकि व्यक्तियों के मानवाधिकारों की समुचित एवं निष्पक्ष रूप से रक्षा संभव हो सके।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. भारत के प्रधानमंत्री ने निरंतर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रणाली का आह्वान किया है। इस संदर्भ में भारत जैसे देश में एक साथ चुनाव आयोजित कराने के लाभों, चिंताओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

The Prime Minister of India has repeatedly called for a system of 'One Nation, One Election'. In this context discuss the advantages, concerns and challenges in holding simultaneous elections in a country like India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के मुद्दों को एक बड़ा सुधार माना जा रहा जिसकी अनुशंसा प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd), संविधान समीक्षा आयोग द्वारा की जा चुकी है। इनमें भारतीय चुनाव प्रणाली के अनेक दोषों को दूर करने की शक्ति है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ :-

(i) अनादर्श आचार संहिता के कारण होने वाली बार-बार विकास बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है।

(ii) चुनावों पर भारी भरकम में देश के धन का व्यय होता है → इससे इस पर कुछ अंकुश लग सकता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(iii) चुनावी के कारण कर्मचारियों के नियोजन के कारण स्कूलों एवं कार्यालयों के कार्यों में बाधा का निराकरण संभव

(iv) व्यक्ति को केवल एक बार वोट डालने जाना होगा → वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है।

चिंताएँ :-

(i) इसके कारण कई बार क्षेत्रीय मुद्दें दबी हो सकते हैं या कई बार केवल राष्ट्रीय।

(ii) देश में छोटी एवं क्षेत्रीय पार्टियों के हितों की अनदेखी होने के संभावना → केवल राष्ट्रीय दलों को ही ज्यादा लाभ की आशंका।

(iii) जनता को राज्य एवं केन्द्र सरकार के मूल्यांकन का 5 वर्ष में एक ही अवसर मिलेगा →

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

जवाबदेही कम होने की आशंका

चुनौतियाँ

(i) भारत की विशाल जनसँख्या → भारी मात्रा में 'EVM' एवं मानव संसाधन की आवश्यकता

(ii) राज्यों के मध्य सहमति बनाना कठिन
↓
'संघात्मक व्यवस्था' की चुनौतियाँ

(iii) भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की आवश्यकता
↓
बाहरी शक्ति व सीमा सुरक्षा की चुनौतियाँ

(iv) राज्यों की अनेक विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने व घटाने की चुनौतियाँ

यह सुधार एक बड़ा एवं युगांतकारी सुधार है जिस पर विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों एवं जनता के बीच विचार-विमर्श होना चाहिए। इसके पश्चात ही समुचित निर्णय का निर्माण करना चाहिए और चुनौतियों का त्वरित समाधान करना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

14. आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The launch of Ayushman Bharat scheme is a significant step towards universal health coverage in India. Critically analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत' का शुभारंभ किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य सभी को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर मानव विकास को बढ़ाना है।

आयुष्मान भारत
- ~~[illegible]~~ चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा
- देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान

आयुष्मान भारत के लाभ:-

(i) गरीब व वंचित जनता को तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में आसानी → अब उनके जेब से स्वास्थ्य खर्च में

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कमी आने की संभावना → गरीबी में जाने से बचाव

(ii) यह योजना देश की लगभग 40% जनसंख्या को प्रभावित करने की क्षमता रखती है → स्वस्थ मानव पूँजी का विकास

(iii) स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएँ → निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच

(iv) लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में चयन की स्वतंत्रता

(v) स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च।

चुनौतियाँ :

(i) लक्षित लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया का कठिन होना

(ii) निजी क्षेत्र की सेवाओं का सरकार द्वारा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वैच्छिक आधार पर मूल्य निर्धारण → निजी अस्पताल इससे खुश नहीं

(iii) लोग निजी क्षेत्र के अस्पतालों में इलाज को वरीयता देंगे → सरकारी अस्पतालों की क्षमता का प्रयोग नहीं

(iv) फ्रॉड बीमा दावों के बढ़ने की आशंका

(v) योजना के लिए भारी मात्रा में वित्तीय आवश्यकता
↓
राजकीय घाटा बढ़ने की आशंका

निःसंदेह यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी साबित हो सकती है परंतु इसके लिए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का तुरंत समाधान करना होगा तभी स्वस्थ मानव पूँजी के निर्माण के साथ-साथ सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति (लक्ष्य 3) संभव हो सकेगी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

15. सरकार की संसदीय प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के क्या कारण थे? (250 शब्द) 15

What are the merits and demerits of the parliamentary system of government? What were the reasons for adopting parliamentary system in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत एक संसदीय लोकतंत्र जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के समूह द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। संविधान निर्माण के समय विश्व की प्रचलित सभी व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के पश्चात इस व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया गया था।

संसदीय प्रणाली के गुण:

(i) इसमें जनता के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों को उठा सकते हैं जो अन्य प्रणाली में कठिन है → इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा

(ii) भारत भाषायी, धार्मिक, नृजातीयता इत्यादि के आधार पर विविधता वाला देश है जिसकी रक्षा के लिए यह प्रणाली उपयुक्त प्रतीत

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

होती है।

(iii) भारत की विशाल जनसंख्या के कारण एवं साथ एक पद के लिए वोटिंग करवाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है परंतु लॅंसडीय प्रणाली में वे केवल अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि को ही चुनते हैं।

b

दोष :-

(i) इस प्रणाली में निर्णय निर्माण में विलंब होता है क्योंकि सभी लोगों के विचारों पर विचार- विमर्श करना पडता है।

(ii) कई बार स्वार्थी हितों की वजह से अनावश्यक रूप से कानून निर्माण व निर्णय लेने की प्रक्रिया में बार- बार बाधा उत्पन्न की जाती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

(iii) क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलने की संभावना होती है तथा इन मुद्दों को लेकर संसद में बाधा डालने का प्रयास होता है।

संसदीय प्रणाली को अपनाने के कारण·

(i) भारत की विशाल जनसंख्या एवं भौगोलिक, सामाजिक, भाषायी इत्यादि विविधता

(ii) देश की अधिकांश जनसंख्या का निरक्षर होना

(iii) हमारे नेता औपनिवेशिक काल के दौरान प्रचलित संसदीय प्रणाली से अभ्यस्त थे। इसलिए इसका क्रियान्वयन आसान था।

संविधान लागू होने के पश्चात संसदीय प्रणाली ने सफलतापूर्वक कार्य किया है हालाँकि समय के साथ अनेक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनका तीव्र समाधान करना आवश्यक है ताकि इस प्रणाली की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. यद्यपि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच एक स्वस्थ संबंध सुशासन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में दोनों के मध्य कई संघर्षपूर्ण क्षेत्र विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Though a healthy relationship between the political executive and the permanent executive is critical for good governance but in practice there are multiple conflict areas in the relationship between the two. Discuss. (250 words) 15

राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका जिनका निर्वाचन निश्चित अवधि के लिए किया जाता है परंतु स्थायी कार्यपालिका अर्थात् नौकरशाही एक स्थायी व्यवस्था है जिनका चयन एक ही बार किया जाता है।

परंतु इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच समय-समय पर अनेक संघर्ष देखने को मिलते हैं जो सुशासन के मार्ग में बाधा का कार्य करते हैं।

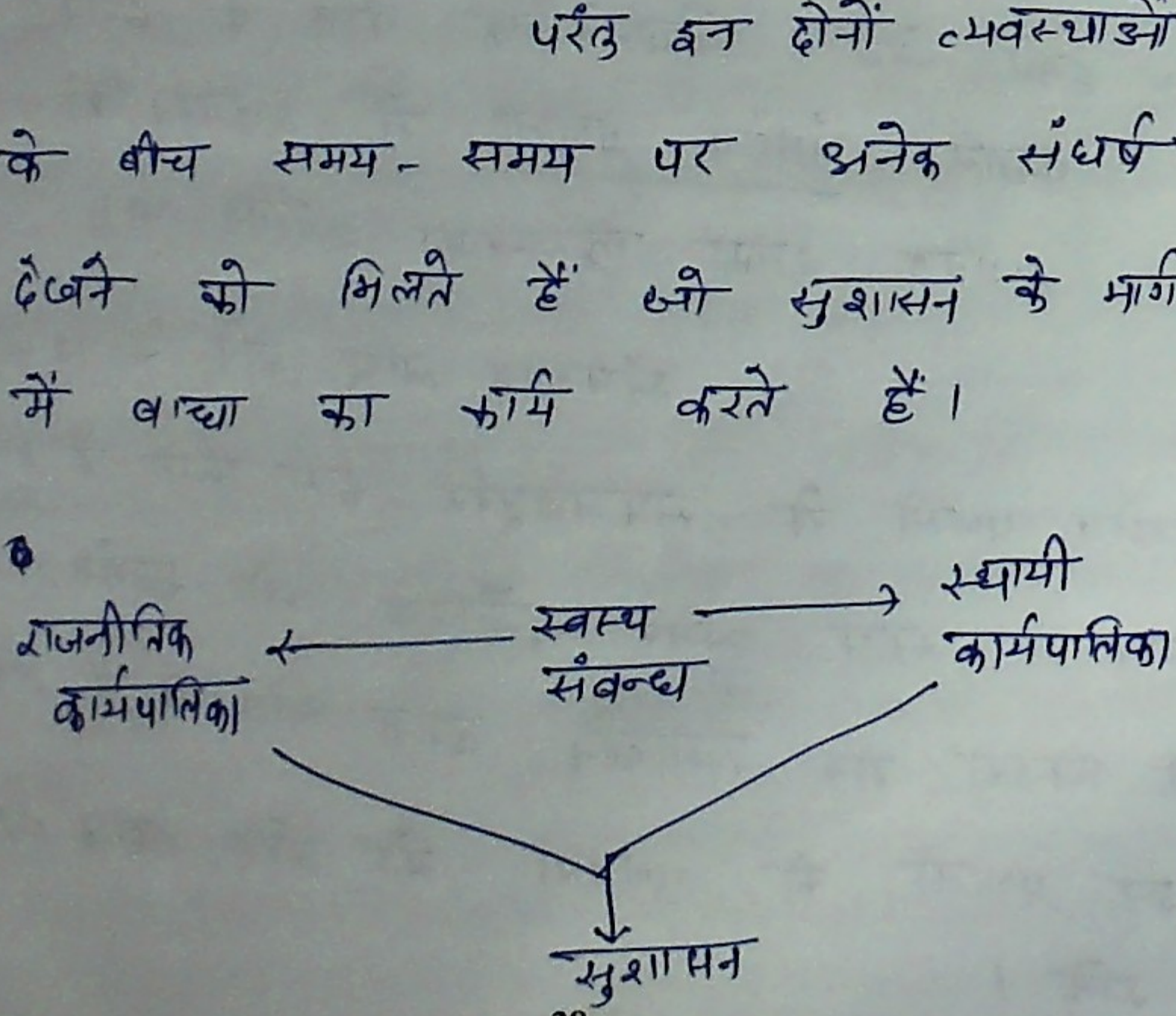

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वस्थ संबंधों के लाभ :-

(i) निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तेज होती है तथा बाधाएँ कम होती हैं

(ii) निर्णय निर्माण में जमीनी अनुभव (राजनेता) एवं विशेषज्ञता (नौकरशाह) का समावेश होता है जिससे एक उत्कृष्ट नीति का निर्माण होता है।

(iii) जनता की माँग का समुचित रूप से नौकरशाहों तक पहुँचना

हानियाँ :-

(i) इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है क्योंकि वे आपस में एक दूसरे के गलत कृत्यों को छुपा सकते हैं।

(ii) सिविल सेवकों (नौकरशाहों) की राजनीतिक तटस्थता के मूल्य पर संकट

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संघर्षपूर्ण क्षेत्र

(i) सिविल सेवा सुधार (अनुच्छेद 311)

(ii) लैटरल एंट्री का मुद्दा - इसकी वजह से नौकरशाह अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और उसका विरोध कर रहे हैं।

इसलिए इन दोनों अवस्थाओं के बीच तुरंत सभी मुद्दों का समाधान कर स्वस्थ संबन्धों का विकास करना चाहिए परंतु इसी बीच नौकरशाहों को अपने 'राजनीतिक तटस्थता' के मूल्य को बनाये रखना चाहिए ताकि सुशासन की प्राप्ति द्वारा जनकल्याण को अधिकतम किया जा सके।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

17. वैकल्पिक विवाद समाधान (ए.डी.आर.) तंत्र के कई लाभ होने के बावजूद भारत में इसकी संभावनाओं का पूर्णत: उपयोग करना शेष है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite having numerous advantages, the potential of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism remains underutilized in India. Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था के बाहर ही पार्टियों के मध्य विवादों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

प्रमुख ए.डी.आर. :

(i) मध्यस्थता (Arbitration)

(ii) सुलह

(iii) मीडिएशन

(iv) लोक अदालत

भारत में यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही विद्यमान है जिसमें अनेक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया गया है। इस व्यवस्था के अनेक लाभ निम्नलिखित हैं—

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

(i) इससे न्यायपालिका पर दबाव में कमी आती है जो पहले ही केसों की भारी भरमार में विलंबता से जूझ रही है।

(ii) इससे समाधान प्रक्रिया में तीव्रता आ सकती है जिससे भारत में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा → व्यापार करने की सुगमता में वृद्धि होगी।

(iv) भारत में एक व्यवस्थित 'A·D·R' तंत्र का विकास होगा → मानव संसाधनों का विकास तथा रोजगार सृजन ↑

परंतु अभी भी बहुत कम मामलों का समाधान इसके माध्यम से किया जाता है क्योंकि इस व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं-

(i) इसमें दोनों पक्षों की हमेशा संतुष्टि नहीं हो पाती

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) भारत में पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित 'ADR तंत्र' का अभाव

(iii) संस्थागत तंत्र व मानव संसाधनों का अभाव

(iv) निर्णयों के लिए विशेषज्ञ मध्यस्थों का अभाव

(v) सुप्रीम कोर्ट में अपील → ADR तंत्र की असफलता

इसी के समाधान एवं भारत को वैकल्पिक विवाद समाधान के एक उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए 'नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र अधिनियम, 2019' को पारित किया गया है ताकि एक विशेषज्ञ एवं सुव्यवस्थित 'ADR तंत्र' की स्थापना कर निवेशकों के विश्वास को जीता जा सके।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत के लिये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों को रद्द करने के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While mentioning the key provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019, discuss the possible implications of scrapping of special provisions under Article 370 for India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this mar

आजादी के बाद के सबसे बड़े मुद्दे कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधान

(i) जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित करना ये हैं— जम्मू व कश्मीर, लद्दाख।

(ii) जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा

(iii) लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा

इसके साथ ही 370 के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

क्लॉज 1 को छोड़कर बाकी सब को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके साथ ही अनुच्छेद 35A भी स्वतः समाप्त हो गया।

अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान रद्द करने के सकारात्मक निहितार्थ-

(i) इससे भारत की एकता व अखण्डता को सुदृढ़ता मिलेगी तथा जम्मू-कश्मीर व बाकी भारत के बीच एक सैद्धांतिक अलगाव समाप्त होने की आशंका है

(ii) शादी के बाद अपनी संपत्ति से वंचित हो जाने वाली कश्मीरी महिलाओं को अब संपत्ति का अधिकार मिलेगा (अनुच्छेद 14 का पालन)

(iii) कश्मीर में निवेश बढ़ने की संभावना है जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iv) पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद व अलगाववाद पर अंकुश लगने की संभावना

नकारात्मक निहितार्थ

(i) अनेक विशेषज्ञों की राय है कि इस प्रावधान को हटाने के लिए समुचित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

(ii) अलगाववादी नेता इसका इस्तेमाल वहाँ की जनता को भड़काने में कर सकते हैं

(iii) वहाँ की जनता में विश्वास की भावना जगाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य।

सैद्धांतिक रूप से तो कश्मीर के अलगाव को दूर करने का कदम तो उठा लिया गया है परंतु कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतकर व्यवहारिक रूप में भारत के साथ उनका एकीकरण अभी शेष है जो एक व्यवहारिक समाधान की मांग करती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

19. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मालदीव में एक नई सरकार की स्थापना के साथ ही भारत-मालदीव के बीच संबंधों में मतभेद समाप्त हो गया है? (250 शब्द) 15

With the inauguration of a new government in Maldives, do you agree that the rough patch in the relationship between India-Maldives is over? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

एक लंबे संघर्ष एवं विरोध के पश्चात मालदीव में नई लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। इसका भारत - मालदीव संबन्धों पर गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है क्योंकि हिन्द महासागर में मालदीव भारत के लिए अनेक अर्थों में एक महत्वपूर्ण देश है।

नई सरकार से भारत के लाभ :-

(i) हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सहायता मिलने की संभावना क्योंकि नई सरकार ने चीन को आवंटित जमीन की लीज को रद्द कर दिया है।

(ii) भारत के हजारों लोग मालदीव में कार्य करते है जिनके हितों की रक्षा नई सरकार के आने से होगी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

(iii) भारत एवं मालदीव के बीच अनेक निवेश एवं व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं (मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान)

(iv) मालदीव भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार का कार्य कर सकता है तथा मालदीव में भारतीय निवेश के लिए काफी संभावनाएँ हैं।

(v) भारत-मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से हवाई अड्डे का विकास

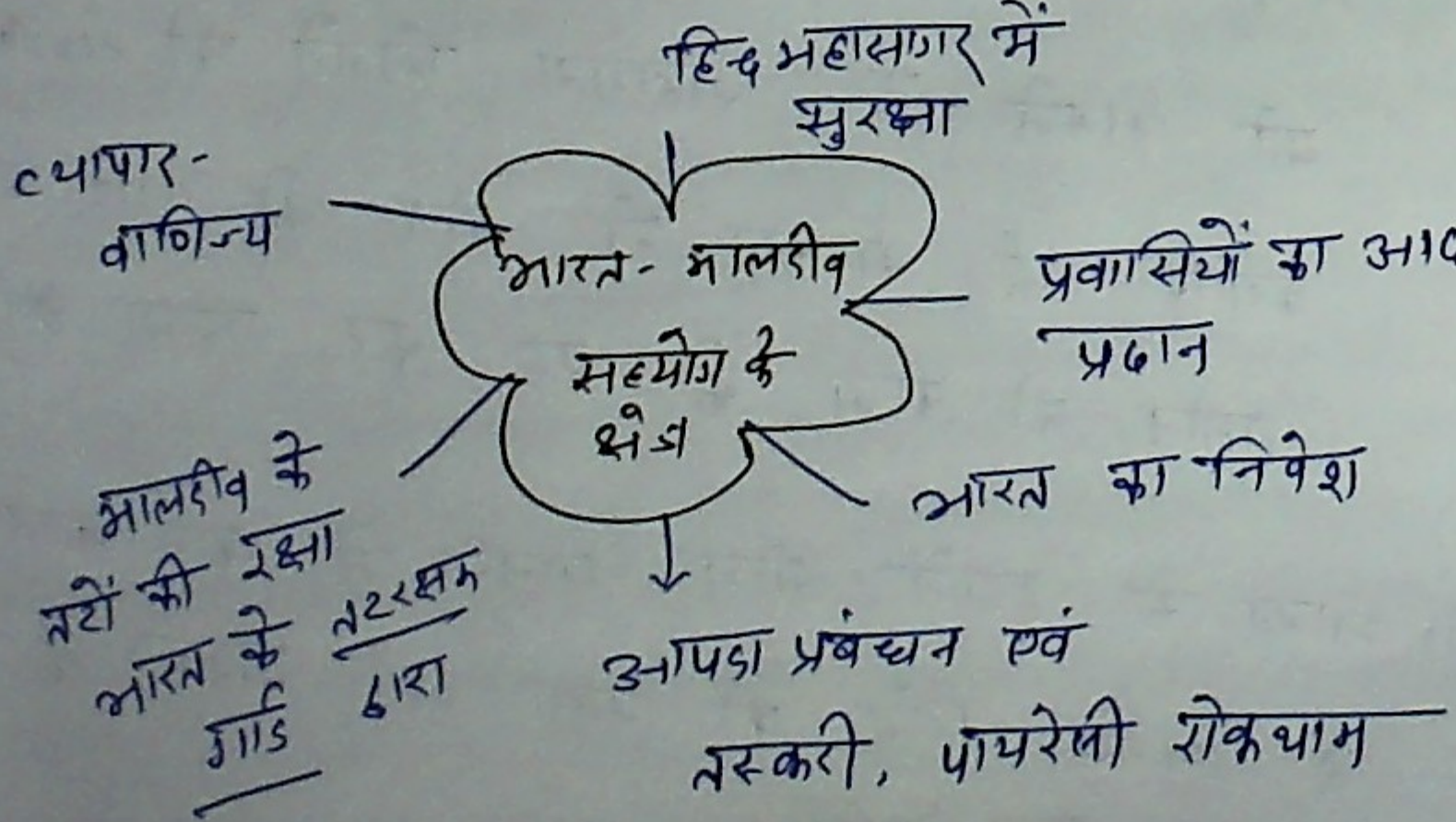

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विद्यमान चुनौतियाँ :-

(i) भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते को सफल रूप से हस्ताक्षर कर लागू करना

(ii) मालदीव को हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए चीन के विपक्ष में खड़ा करना

(iii) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना

(iv) व्यापार को संभावित क्षमता तक बढ़ाने का प्रयास करना

ऑपरेशन कैक्टस के अलावा भी अनेक मौकों पर भारत हमेशा मालदीव का सहयोगी व हितैषी रहा है परंतु हाल ही में कुछ वर्षों से उत्पन्न गतिरोध को दूर करके आपसी संबंधों का पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। मुक्त व्यापार समझौता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस.सी.) के सुधारों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? इन सुधारों को लागू करने में विलंब के क्या कारण हैं? (250 शब्द) 15

What is India's perspective on the United Nations Security Council (UNSC) reforms? What are the reasons for delay in bringing out these reforms? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लि चाहिये।

(Candidate must write on this mar

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते है जो विश्व शांति एवं समृद्धि की स्थापना के उद्देश्य से कार्य करते है।

समय-समय पर अनेक देशों मुख्यतः 'G-4' देशों द्वारा सुरक्षा परिषद में ~~अनेक मांग~~ सुधार की मांग की जाती रही है।

सुधार के प्रमुख मुद्दे-

(i) सुरक्षा परिषद में सभी महाद्वीपों का समान प्रतिनिधित्व नहीं

(छोटे से यूरोप से दो स्थायी सदस्य परंतु विस्तृत अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

से एक भी सदस्य नहीं

(ii) वीटो पावर - लोकतांत्रिक वातावरण में किसी 1 सदस्य द्वारा निर्णय निर्माण प्रक्रिया को पूर्णत: प्रभावित करना तार्किक प्रतीत नहीं होता

(iii) भारत भी अपनी स्थायी सीट के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि बदलती विश्व व्यवस्था में वह भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है

(iv) सुरक्षा परिषद कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे ईराक पर अमेरिका का आक्रमण, दक्षिणी चीन सागर में चीन का कब्जा इत्यादि का समाधान नहीं कर पाई।

भारत का दृष्टिकोण

(i) स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए तथा सभी सदस्यों को वीटो पावर मिलनी चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

(ii) सुरक्षा परिषद में सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए

(iii) विकासशील व विकसित देशों का संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए

(iv) निर्णय निर्माण प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए

इसी संदर्भ में भारत ने समान हितों के समूह 'जी-4' का गठन किया है तथा विश्व के बड़े देशों का समर्थन अपने पक्ष में ले रहा है ताकि सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिल सके। इसके लिए चीन के प्रतिरोध को सफलतापूर्वक तोड़ना एक चुनौतिपूर्ण कार्य होगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लि
चाहिये।
(Candidate must
write on this mar

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation